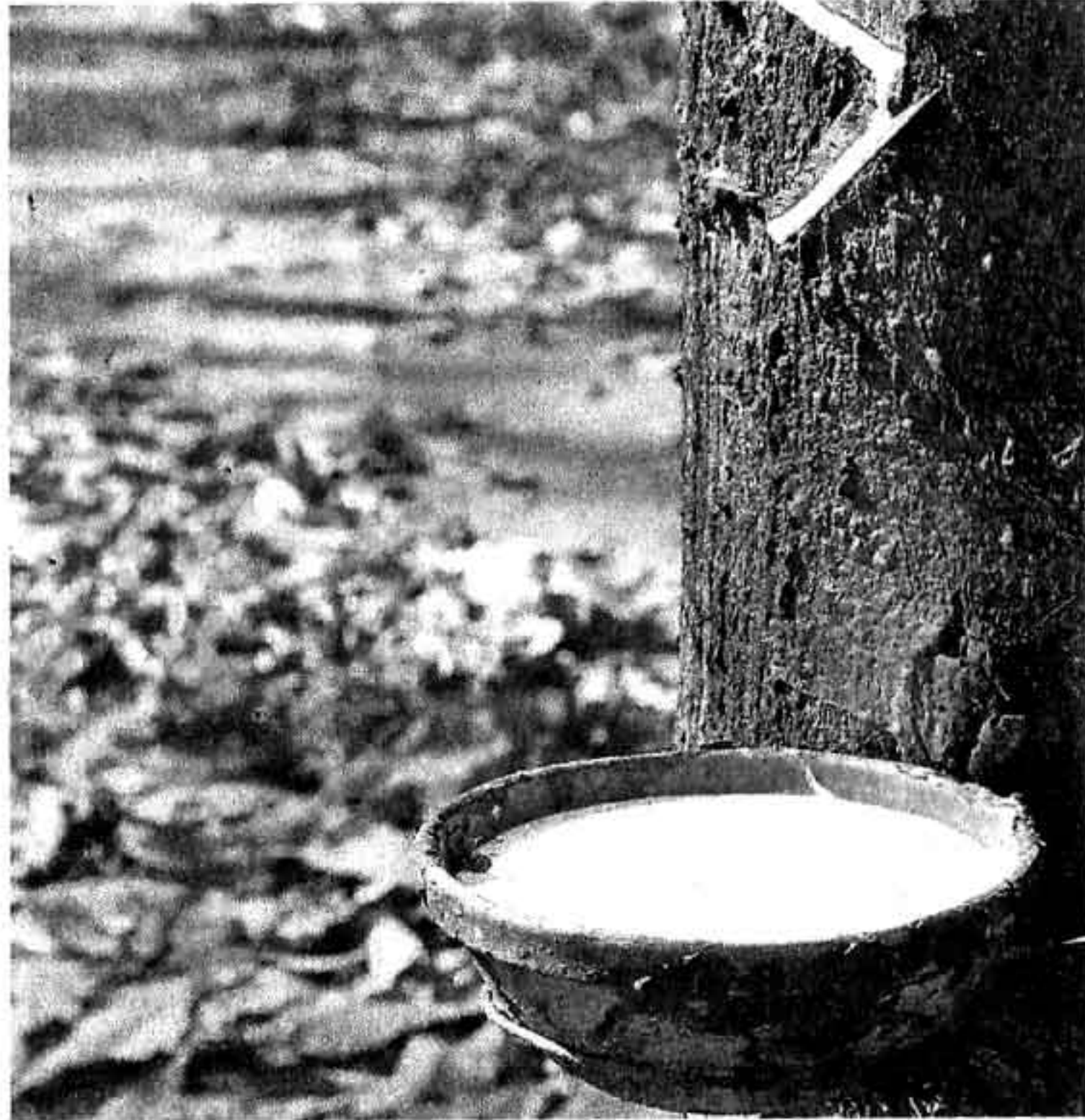


# कीमतें गिरने से रबड़ प्लांटर बेहाल, सरकार पर टिकी आस



**पिछले साल बाढ़ आने और सरकार की ओर से मदद न मिलने से केरल में रबड़ पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका**

पी के कृष्णकुमार | रामापुरम |

सस्ते इम्पोर्ट और घटती कीमतों से परेशान रबड़ प्लांटर्स मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से रबड़ पॉलिसी घोषित करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पिछले वर्ष हुई भारी बारिश से स्थिति और खराब हो गई है। बारिश के कारण बाढ़ आने और सरकार की ओर से मदद न मिलने से केरल में रबड़ पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है।

इससे लोन पर डिफॉल्ट हो रहे हैं, ट्रेडर्स को दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं और दुकानदारों की बिक्री लगभग आधी रह गई है। बहुत से लोगों ने आजीविका के लिए मवेशी रखने शुरू कर दिए हैं और वे दूध बेच रहे हैं या

रोजगार गारंटी योजना के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि नेशनल रबड़ पॉलिसी चार वर्षों से अटकी हुई है। इससे इम्पोर्ट में कमी आने और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश किए जाने के साथ ही रबड़ को कृषि उत्पादन के तौर पर स्वीकृति मिलने की उम्मीद थी। इंडियन फार्मर्स मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी सी सिरिएक ने बताया, 'पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामण ने इसकी घोषणा के लिए रबड़ बोर्ड कमेटी को दिल्ली बुलाया था।

लेकिन इसके बाद वह अपने वादे से पीछे हट गई और कहा था कि केवल रबड़ के लिए पॉलिसी लाना संभव नहीं है।' सिरिएक रबड़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं। उन्होंने इस बारे में कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु से भी मुलाकात की थी लेकिन पॉलिसी की अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

रबड़ की यील्ड में गिरावट आई है। रबड़ की टैपिंग करने वाले संजय चक्कानकल एक पेड़ के लिए 2 रुपये लेकर एक दिन में 400-500 पेड़ों से लेटेक्स निकालते थे। लेकिन अब वह अपनी आमदनी का आधा हिस्सा रबड़ एस्टेट मालिक को देते हैं जिनसे उनका

व्यवसाय फायदे में बना रहे। बहुत से अन्य भी इसी तरह के भुगतान की व्यवस्था अपना रहे हैं क्योंकि रबड़ के प्लांटेशन नें से 90 पर्सेंट से अधिक छोटे किसानों की हैं। बड़ बनाने के लिए लेटेक्स प्रमुख कच्चा माल होता है।

रबड़ का प्लांटेशन करने वाले एस कुमार ने बताया, 'सितंबर में यील्ड एक दिन में 10 किलोग्राम की थी, जो अक्टूबर में गिरकर 7.4 किलोग्राम रह गई।' इससे बहुत से रबड़ ट्रेडर्स को कारोबार से बाहर होना पड़ रहा है। चोलिकारा ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले पी जे मथाचन ने बताया, 'हम 5 लोड (प्रत्येक 10 टिन) स्क्रेप रबड़ प्रतिदिन भेजते थे। अब यह मात्रा घटकर आधी

**किसानों की शिकायत, चार वर्षों से अटकी हुई है नेशनल रबड़ पॉलिसी**

हो गई है।'

केरल ग्रामीण बैंक की ब्रांच मैनेजर मर्सी एम जोस ने बताया कि लोन डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं।

बैंक अपने कस्टमर्स को 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का कर्ज देता है। मर्सी ने कहा, 'कस्टमर्स जानबूझ कर डिफॉल्ट नहीं कर रहे लेकिन उनके पास कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं है।'